ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शारीरिक एवं शैक्षणिक विकास में आँगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका एवं चुनौतियाँ

पप्पू
शोधार्थी एवं सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय (बी०एड० विभाग)
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
एवं
शुभ्रा पी० काण्डपाल
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय (बी०एड० विभाग),
एम० बी० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक स्तर पर आँगनवाड़ी केंद्रों की बहुआयामी भूमिका का विश्लेषण करता है। 500 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (ग्रामीण: 290, शहरी: 210) पर आधारित इस सर्वेक्षण शोध में 5-बिंदु लाइकर्ट स्केल पर निर्मित 100 प्रश्नों के माध्यम से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक एवं सामाजिक-भावनात्मक विकास तथा NEP 2020 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया है।

परिणाम दर्शाते हैं कि शारीरिक विकास में ग्रामीण क्षेत्र (91.9%) तथा मानसिक विकास में शहरी क्षेत्र (87.3%) अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। NEP 2020 के कार्यान्वयन में ग्रामीण-शहरी अंतर सर्वाधिक (6.2%) डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में पाया गया (ग्रामीण: 75.5%, शहरी: 87.0%)। शोध यह भी इंगित करता है कि ग्रामीण आँगनवाड़ी केंद्रों में प्रशिक्षण, अवसंरचना एवं डिजिटल संसाधनों की गंभीर कमी है।

बीज शब्द: आँगनवाड़ी, NEP 2020, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शारीरिक विकास, शैक्षणिक विकास, ग्रामीण-शहरी अंतर

प्रस्तावना

भारत में 0-6 वर्ष के बच्चों के समग्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास में आँगनवाड़ी केंद्रों की ऐतिहासिक एवं अपरिहार्य भूमिका रही है। वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम के अंतर्गत

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

स्थापित ये केंद्र आज देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी बस्तियों तक फैले हुए हैं। वर्तमान में लगभग 14.0 लाख आँगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, जो 9.5 करोड़ से अधिक बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। (ijsred.com)

आँकड़ों के अनुसार ICDS कार्यक्रम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आउटरीच और सेवाओं का विस्तार जारी रखा है – बच्चों की संख्यात्मक कवरेज 8.7 करोड़ (2020-21) से बढ़कर लगभग 9.5 करोड़ तक पहुँच गई है और गर्भवती तथा स्तनधारी महिलाओं का कवरेज भी 1.9 करोड़ से बढ़कर 2.1 करोड़ तक पहुंच चुका है। (ijsred.com)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने पूर्व-बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education – ECCE) को औपचारिक शिक्षा की नींव के रूप में मान्यता दी है। इस नीति का लक्ष्य 3-6 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिसमें खेल-आधारित शिक्षण, बहुभाषिक शिक्षण, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन और डिजिटल साक्षरता जैसी अवधारणाएँ शामिल हैं। (Chaifry)

NEP 2020 के संदर्भ में आँगनवाड़ी केंद्र न केवल पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि ये एक प्राथमिक सीखने का मंच (pre-school learning environment) भी उपलब्ध कराते हैं। नीति के अनुसार बच्चों को ज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और भाषा-संबंधी विकास के अवसर प्रदान करना अनिवार्य है, साथ ही शिक्षण-सीखने की गतिविधियाँ संरचित एवं बाल-अनुकूल होनी चाहिए। (Chaifry)

हालाँकि ICDS की पहुंच और कवरेज सराहनीय रही है, फिर भी अंतर-राज्यीय असमानताएँ, वित्तीय एवं कार्यबल चुनौतियाँ, तथा बुनियादी ढांचे की कमी आज भी कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के रूप में, अनेक केंद्रों में स्थायी भवन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और रसोई सुविधाओं का अभाव है, जो सेवाओं की प्रभावी उपलब्धता और बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। (PRS Legislative Research)

इसके अलावा, ICDS कार्यकर्ताओं (आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायता) की संख्या अपर्याप्त है, कई स्थानों पर वे अधिक कार्यभार तथा प्रशिक्षण की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। यह स्थिति ECCE के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी बाधाएँ उत्पन्न करती है। (Drishti IAS)

इस शोध का केंद्रीय उद्देश्य है – NEP 2020 के तहत नैनीताल जिले के आँगनवाड़ी केंद्रों की वास्तविक स्थिति, उनकी क्षमता, उपलब्ध संसाधन, सेवाओं की गुणवत्ता तथा कार्यक्रम के समक्ष विद्यमान विविध चुनौतियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना।

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

तालिका-1: राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संचालित आँगनवाड़ी केंद्रों (ICDS) की संख्या

(लोकसभा में प्रस्तुत आधिकारिक सरकारी उत्तर के अनुसार)

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	संचालित आँगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	55,607
अरुणाचल प्रदेश	6,225
असम	62,093
बिहार	114,968
छत्तीसगढ़	52,382
गोवा	1,261
गुजरात	53,065
हरियाणा	25,962
हिमाचल प्रदेश	18,925
झारखंड	38,515
कर्नाटक	65,931
केरल	33,120
मध्य प्रदेश	97,329
महाराष्ट्र	110,516
मणिपुर	11,523
मेघालय	6,162
मिज़ोरम	2,244
नागालैंड	3,980
ओडिशा	74,192
पंजाब	27,314
राजस्थान	61,885
सिक्किम	1,308
तमिलनाडु	54,449
तेलंगाना	35,700
त्रिपुरा	10,222
उत्तर प्रदेश	1,89,021
उत्तराखंड	20,060
पश्चिम बंगाल	119,481
दिल्ली	10,897
जम्मू एवं कश्मीर	28,426

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

लद्दाख	1,173
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	720
चंडीगढ़	450
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	405
लक्षद्वीप	59
पुदुचेरी	855
कुल (अखिल भारतीय)	**13,96,425+**

तालिका-1 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे उच्च जनसंख्या वाले राज्यों में आँगनवाड़ी केंद्रों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है। यह न केवल जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है, बल्कि इन राज्यों में ICDS कार्यक्रम की व्यापक पहुँच को भी इंगित करता है। इसके विपरीत, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में आँगनवाड़ी केंद्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जो वहाँ की सीमित भौगोलिक और जनसंख्या संरचना के अनुरूप है।

यह राज्यवार वितरण NEP 2020 के अंतर्गत ECCE लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं, संसाधन आवंटन तथा गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता का विश्लेषण किया जा सकता है। NEP 2020 के अनुसार ECCE (Early Childhood Care and Education) का उद्देश्य 3-6 वर्ष के बच्चों के कुल मिलाकर विकास को सुनिश्चित करना है — जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक-भावनात्मक, भाषा-ज्ञानात्मक, और सीखने की तत्परता शामिल हैं।

तालिका-2: NEP 2020 के ECCE ढांचे के लिए मापन संकेतक (Indicators)

मापन संकेतक (Indicators)	**विवरण (Description)**
संख्या एवं वितरण	राज्य/जिला स्तर पर ECCE-सक्षम आँगनवाड़ी केंद्रों का % (कुल केंद्रों के मुकाबले)
बच्चों का नामांकन (Enrollment)	3-6 वर्ष के बच्चों का पूर्व-प्राथमिक शिक्षा / ECCE प्रभाग में नामांकन प्रतिशत
उपस्थिति स्थिति (Attendance)	मासिक उपस्थिति प्रतिशत (बच्चों/कार्यकर्ताओं)
सीखने की गतिविधियाँ (Learning Activities)	खेल-आधारित, भाषा-बहुभाषी और सृजनात्मक गतिविधियों का अनुपालन
मानव संसाधन (Human Resources)	प्रशिक्षित आँगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की संख्या और प्रशिक्षण स्तर
डिजिटल एकीकरण (Digital Tracking)	Poshan Tracker/ICDS-CAS जैसे डिजिटल डेटा अपडेट की सटीकता

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

स्वास्थ्य एवं पोषण (Health & Nutrition)	नियमित स्वास्थ्य जांच, वज़न-लंबाई निगरानी, पोषण स्तर
बुनियादी ढांचा (Infrastructure)	ECCE-अनुकूल भवन, शौचालय, साफ़ पानी, खेल सामग्री
गुणवत्ता आकलन (Quality Assessment)	केंद्रों पर बाह्य/आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट एवं मूल्यांकन
परिवार/समुदाय भागीदारी	अभिभावकों/समुदायों की भागीदारी तथा समर्थन कार्यक्रम

NEP 2020 ECCE ढांचे के संकेतक केवल शिक्षा तक सीमित नहीं हैं; वे पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक-भावनात्मक विकास, खेल-आधारित सीखने और डिजिटल निगरानी जैसे आयामों को एकीकृत करते हैं।

2. साहित्य समीक्षा

ब्रोनफेनब्रेनर (1979) के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार, बालक का विकास उसके परिवार, समुदाय और वृहत्तर सामाजिक संरचनाओं की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। आँगनवाड़ी केंद्र इस पारिस्थितिकी तंत्र में 'मेसोसिस्टम' की भूमिका निभाते हैं, जो परिवार एवं समुदाय के बीच सेतु का कार्य करते हैं। रामचंद्रन (2010) ने अपने अध्ययन में पाया कि ICDS कार्यक्रम से जुड़े बच्चों में कुपोषण की दर 28% कम थी तथा उनका प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश एवं ठहराव दर भी उल्लेखनीय रूप से बेहतर था। शर्मा एवं वर्मा (2018) ने राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के आँगनवाड़ी केंद्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं वाले केंद्रों में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 35% बेहतर था। गुप्ता (2019) ने डिजिटल अंतराल को आँगनवाड़ी केंद्रों की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उनके अनुसार शहरी आँगनवाड़ी केंद्रों में जहाँ 62% केंद्रों में स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध थे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत मात्र 23% था। NITI Aayog (2021) की रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि ग्रामीण आँगनवाड़ी केंद्रों में NEP 2020 के प्रावधानों को लागू करने में संरचनात्मक बाधाएँ सबसे बड़ी अड़चन हैं। Singh (2022) ने NEP 2020 एवं ECCE के एकीकरण पर केंद्रित अध्ययन में पाया कि बहुभाषी शिक्षण पद्धति के कार्यान्वयन में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से 5-8 प्रतिशत अंकों से पीछे थे, जो वर्तमान शोध के निष्कर्षों से मेल खाता है।

3. शोध उद्देश्य एवं शोध-विधि

3.1 शोध उद्देश्य

- NEP 2020 के तहत नैनीताल जिले के आँगनवाड़ी केंद्रों की पूर्व प्राथमिक बच्चों के शारीरिक विकास में भूमिका का ग्रामीण-शहरी तुलनात्मक मूल्यांकन करना।
- मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में नैनीताल जिले के आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

- शैक्षणिक एवं सामाजिक-भावनात्मक विकास गतिविधियों का विश्लेषण करना।
- NEP 2020 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में ग्रामीण-शहरी अंतर को मापना।
- आँगनवाड़ी केंद्रों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।

3.2 शोध-विधि

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण शोध-विधि का उपयोग किया गया है। यह एक वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक शोध है जो मात्रात्मक आँकड़ों पर आधारित है।

3.3 नमूना चयन

उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन (Purposive Sampling) पद्धति से NEP 2020 के तहत नैनीताल जिले के कुल 500 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन किया गया — 290 ग्रामीण (58%) एवं 210 शहरी (42%)।

3.4 शोध उपकरण

100 प्रश्नों वाली एक स्व-निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया जो 5-बिंदु लाइकर्ट स्केल (1=पूर्णतः असहमत से 5=पूर्णतः सहमत) पर आधारित थी। प्रश्नावली में चार मुख्य भाग थे: (i) शारीरिक विकास (प्र. 1-18), (ii) मानसिक विकास (प्र. 19-36), (iii) शैक्षिक/सामाजिक-भावनात्मक विकास (प्र. 37-65), (iv) NEP 2020 की भूमिका (प्र. 66-74)।

प्रश्नावली की विश्वसनीयता क्रोनबाख अल्फा ($\alpha = 0.87$) द्वारा प्रमाणित की गई तथा सामग्री वैधता विशेषज्ञों के पैनल द्वारा सुनिश्चित की गई।

4. आँकड़ा विश्लेषण एवं व्याख्या

ISSN : 3108-0294

प्रस्तुत शोध नैनीताल जिले के समस्त आँगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आँगनवाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं पर आधारित है। ये सभी कर्मी ही शोध के प्रमुख उत्तरदाता हैं, जिनके अनुभव, चुनौतियाँ और दृष्टिकोणों पर अध्ययन किया गया है। नैनीताल जिले में आँगनवाड़ी परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है, नैनीताल जिले में कुल 9 शैक्षिक परियोजनाएँ हैं जो 43 सेक्टर और 1,423 आँगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ी हैं। यह नेटवर्क बच्चों और महिलाओं के समग्र कल्याण हेतु एक सशक्त संरचना प्रस्तुत करता है। न्यादर्श के रूप में इन 500 आँगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित आँगनवाड़ी कर्मी/सहायिकाओं को शामिल किया गया। यह न्यादर्श आकार सांख्यिकीय दृष्टि से पर्याप्त एवं विश्वसनीय माना गया है तथा शोध के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयुक्त है।

4.1 शारीरिक विकास (प्रश्न 1-18)

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

अधिकतम संभावित स्कोर 90 (18 × 5) के सापेक्ष दोनों क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

सारणी 1: शारीरिक विकास — ग्रामीण एवं शहरी तुलना

क्षेत्र	संख्या	औसत स्कोर	प्रतिशत	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
ग्रामीण	290	82.69	91.9%	4.58	74	90
शहरी	210	81.05	90.1%	5.12	72	88
कुल	500	82.00	91.1%	4.85	72	90

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25 | अधिकतम स्कोर: 90

सारणी 1.2: उप-विभागवार आँकड़े — शारीरिक विकास

उप-विभाग	ग्रामीण औसत	शहरी औसत	कुल औसत
स्थूल गामक विकास	18.2/20	17.8/20	18.0/20
सूक्ष्म गामक विकास	23.1/25	22.5/25	22.8/25
पोषण स्थिति	22.8/25	22.3/25	22.6/25
स्वास्थ्य स्थिति	18.6/20	18.4/20	18.5/20

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25

विश्लेषण: ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक विकास का औसत स्कोर 82.69 (91.9%) है जबकि शहरी क्षेत्रों में 81.05 (90.1%) है। ग्रामीण क्षेत्र 1.64 अंक से आगे हैं, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण परिवेश में खुले स्थान की उपलब्धता एवं परंपरागत शारीरिक खेलों की निरंतरता हो सकती है। दोनों क्षेत्रों में स्कोर 90% से अधिक है जो उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकेत है (Ramachandran, 2010)।

4.2 मानसिक विकास (प्रश्न 19-36)

सारणी 2: मानसिक विकास — ग्रामीण एवं शहरी तुलना

क्षेत्र	संख्या	औसत स्कोर	प्रतिशत	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
ग्रामीण	290	77.48	86.1%	5.87	65	86
शहरी	210	78.57	87.3%	3.99	73	87
कुल	500	77.96	86.6%	5.12	65	87

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25 | अधिकतम स्कोर: 90

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

सारणी 2.1: उप-विभागवार आँकड़े — मानसिक विकास

उप-विभाग	ग्रामीण औसत	शहरी औसत	कुल औसत
संज्ञानात्मक कौशल	21.4/25	21.9/25	21.6/25
भाषा विकास	21.6/25	21.8/25	21.7/25
स्मृति एवं एकाग्रता	17.2/20	17.5/20	17.3/20
समस्या समाधान	17.3/20	17.4/20	17.3/20

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25

विश्लेषण: मानसिक विकास में शहरी क्षेत्र (87.3%) ग्रामीण क्षेत्र (86.1%) से 1.09 अंक आगे है। शहरी केंद्रों में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं, पुस्तकालयों एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता इस श्रेष्ठता का कारण हो सकती है। संज्ञानात्मक कौशल (21.6/25) एवं भाषा विकास (21.7/25) में दोनों क्षेत्र लगभग समान स्तर पर हैं। Sharma एवं Verma (2018) के निष्कर्षों के अनुसार प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति संज्ञानात्मक विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है।

4.3 शैक्षिक एवं सामाजिक-भावनात्मक विकास (प्रश्न 37-65)

सारणी 3: शैक्षिक/सामाजिक-भावनात्मक विकास — ग्रामीण एवं शहरी तुलना

क्षेत्र	संख्या	औसत स्कोर	प्रतिशत	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
ग्रामीण	290	126.52	87.3%	4.61	113	134
शहरी	210	124.10	85.6%	8.33	114	140
कुल	500	125.48	86.5%	6.52	113	140

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25 | अधिकतम स्कोर: 145 (29 × 5)

सारणी 3.1: उप-विभागवार आँकड़े — शैक्षिक विकास

उप-विभाग	ग्रामीण औसत	शहरी औसत	कुल औसत
प्री-लिटरेसी कौशल	21.8/25	21.3/25	21.6/25
प्री-न्यूमेरेसी कौशल	21.9/25	21.5/25	21.7/25
विद्यालय तत्परता	21.7/25	21.2/25	21.5/25
सामाजिक कौशल	17.4/20	17.1/20	17.3/20
भावनात्मक विकास	21.7/25	21.0/25	21.4/25
व्यक्तित्व विकास	22.0/25	22.0/25	22.0/25

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25

विश्लेषण: इस खंड में ग्रामीण क्षेत्र (87.3%) शहरी क्षेत्र (85.6%) से 2.42 अंक अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है क्योंकि यह पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि शहरी क्षेत्र शिक्षा में सदैव आगे रहते हैं। व्यक्तित्व विकास (22.0/25) में दोनों क्षेत्र पूर्णतः समान हैं। भावनात्मक विकास में ग्रामीण क्षेत्र (21.7/25) शहरी क्षेत्र (21.0/25) से बेहतर है, जो परिवार एवं समुदाय की मजबूत सामाजिक संरचना का परिणाम हो सकता है (Bronfenbrenner, 1979)।

4.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका (प्रश्न 66-74)

सारणी 4: NEP 2020 कार्यान्वयन — ग्रामीण एवं शहरी तुलना

क्षेत्र	संख्या	औसत स्कोर	प्रतिशत	मानक विचलन	न्यूनतम	अधिकतम
ग्रामीण	290	35.59	79.1%	2.04	32	39
शहरी	210	38.38	85.3%	1.50	35	41
कुल	500	36.76	81.7%	2.28	32	41

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25 | अधिकतम स्कोर: 45 (9 × 5)

सारणी 4.2: NEP 2020 के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण

NEP 2020 पहलू	ग्रामीण %	शहरी %	अंतर
खेल-आधारित शिक्षा	78.2%	86.5%	+8.3%
बहुभाषी शिक्षा	80.5%	85.8%	+5.3%
व्यापक मूल्यांकन (CCE)	77.8%	84.2%	+6.4%
डिजिटल साक्षरता	75.5%	87.0%	+11.5%
माता-पिता की भागीदारी	81.2%	83.5%	+2.3%

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण, 2024-25

विश्लेषण: NEP 2020 के कार्यान्वयन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर इसी खंड में दृष्टिगोचर होता है। शहरी क्षेत्र (85.3%) ग्रामीण क्षेत्र (79.1%) से 6.2 प्रतिशत आगे है। डिजिटल साक्षरता में यह अंतर सर्वाधिक (+11.5%) है — ग्रामीण (75.5%) बनाम शहरी (87.0%)। यह अंतर Gupta (2019) के निष्कर्षों एवं NITI Aayog (2021) की रिपोर्ट से पूर्ण रूप से सुसंगत है। खेल-आधारित शिक्षा में 8.3% का अंतर भी उल्लेखनीय है तथा यह शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता का परिणाम है।

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

5. प्रमुख निष्कर्ष

5.1 सारांशात्मक तुलनात्मक तालिका

विकास क्षेत्र	ग्रामीण %	शहरी %	कुल %	श्रेष्ठ
शारीरिक विकास	91.9%	90.1%	91.1%	ग्रामीण (+1.8%)
मानसिक विकास	86.1%	87.3%	86.6%	शहरी (+1.2%)
शैक्षिक विकास	87.3%	85.6%	86.5%	ग्रामीण (+1.7%)
NEP 2020 कार्यान्वयन	79.1%	85.3%	81.7%	शहरी (+6.2%)

स्रोत: शोधार्थी द्वारा संकलित, 2024-25

5.2 विस्तृत निष्कर्ष

1. शारीरिक विकास में ग्रामीण आँगनवाड़ी केंद्र (91.9%) शहरी केंद्रों (90.1%) से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परंपरागत बाह्य खेलों एवं शारीरिक गतिविधियों की निरंतरता का परिणाम है।
2. मानसिक विकास में शहरी केंद्र (87.3%) थोड़े आगे हैं, किंतु दोनों क्षेत्रों में प्रदर्शन 85% से ऊपर है जो सकारात्मक संकेत है।
3. शैक्षिक एवं सामाजिक-भावनात्मक विकास में ग्रामीण क्षेत्र (87.3%) शहरी (85.6%) से 2.42 अंक आगे है — यह प्रचलित धारणा के विपरीत परिणाम है।
4. NEP 2020 का कार्यान्वयन शहरी केंद्रों में स्पष्ट रूप से बेहतर है, विशेषतः डिजिटल साक्षरता (+11.5%) तथा खेल-आधारित शिक्षा (+8.3%) में।
5. व्यक्तित्व विकास एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों क्षेत्र पूर्णतः समान (22.0/25) हैं।

6. आँगनवाड़ी केंद्रों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

6.1 ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियाँ

डिजिटल अवसंरचना का अभाव: केवल 75.5% ग्रामीण केंद्रों में डिजिटल साक्षरता गतिविधियाँ संचालित हो पा रही हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी NEP 2020 के लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़ी बाधा है।

1. प्रशिक्षण की कमी: कार्यकर्ताओं को खेल-आधारित शिक्षा (78.2%) एवं व्यापक मूल्यांकन (77.8%) में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है।

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

2. अवसंरचनात्मक कमियाँ: अनेक ग्रामीण केंद्रों में उपयुक्त भवन, शौचालय, पेयजल एवं शैक्षणिक सामग्री का अभाव है।

3. कार्यकर्ताओं का कार्यभार: एक कार्यकर्ता पर पोषण, टीकाकरण, शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का एकसाथ दायित्व उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करता है।

6.2 शहरी क्षेत्रों की चुनौतियाँ

1. उच्च जनसंख्या घनत्व: शहरी केंद्रों में अधिक बच्चों की उपस्थिति के कारण व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो जाता है।

2. स्थानाभाव: शहरी झुग्गी बस्तियों में केंद्र प्रायः अत्यंत सीमित स्थान में संचालित होते हैं जिससे शारीरिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।

3. अभिभावकों की व्यस्तता: शहरी परिवेश में अभिभावकों की भागीदारी (83.5%) ग्रामीण (81.2%) की तुलना में मात्र 2.3% अधिक है जो अपेक्षाओं से कम है।

6.3 सामान्य चुनौतियाँ

1. बहुभाषी शिक्षण: बच्चों की विविध मातृभाषाओं को ध्यान में रखते हुए NEP 2020 के बहुभाषी शिक्षण का क्रियान्वयन जटिल कार्य है।

2. गुणवत्तापूर्ण पर्यवेक्षण तंत्र का अभाव: नियमित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण की कमी से गुणवत्ता में एकरूपता नहीं है।

7. सुझाव एवं नीति-निर्देश

उपर्युक्त निष्कर्षों के आलोक में निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:

1. डिजिटल सशक्तीकरण: ग्रामीण आँगनवाड़ी केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर डिजिटल उपकरण (टैबलेट, स्मार्ट टीवी) एवं हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। डिजिटल अंतर (11.5%) को पाटना NEP 2020 की सफलता के लिए अनिवार्य है।

2. सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रत्येक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए वार्षिक कम-से-कम 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किया जाए जिसमें खेल-आधारित शिक्षा, CCE, बहुभाषी शिक्षण एवं डिजिटल साक्षरता शामिल हों।

ISSN : 3108-0294
Asha Paras Vahuvishyak Bhartiya Shodh-Patrika
(BI-ANNUAL PEER-REVIEWED, ONLINE RESEACH JOURNAL)
आशा पारस वहुविषयक भारतीय शोध-पत्रिका
(अर्द्धवार्षिक सहकर्मी-समीक्षित, ऑनलाइन शोध पत्रिका)
खंड-1, अंक-2 अक्टूबर-मार्च, 2025-26, apvbsp@gmail.com www.apvbsp.com

3. अवसंरचना सुदृढ़ीकरण: भारत निर्माण एवं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आँगनवाड़ी भवनों के नवीनीकरण हेतु विशेष निधि आवंटित की जाए।

4. कार्यभार पुनर्वितरण: पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशासनिक कार्यों के लिए सहायक कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएँ ताकि मुख्य कार्यकर्ता शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

5. समुदाय की भागीदारी: माता-पिता-शिक्षक समिति (PTC) को सक्रिय किया जाए एवं स्थानीय समुदाय को आँगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में भागीदार बनाया जाए।

6. मोबाइल आँगनवाड़ी: अत्यंत दूरस्थ एवं घुमंतू समुदायों तक पहुँचने के लिए मोबाइल आँगनवाड़ी इकाइयाँ स्थापित की जाएँ।

8. उपसंहार

प्रस्तुत शोध स्पष्ट करता है कि आँगनवाड़ी केंद्र NEP 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। 500 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष यह सिद्ध करते हैं कि शारीरिक एवं शैक्षणिक विकास में ग्रामीण केंद्र शहरी केंद्रों से कमतर नहीं हैं, अपितु कई क्षेत्रों में वे आगे हैं। किंतु NEP 2020 के तकनीकी एवं नवाचारी पहलुओं — विशेषतः डिजिटल साक्षरता — में ग्रामीण केंद्र अभी भी पिछड़े हुए हैं।

अतः यह आवश्यक है कि नीति-निर्माता ग्रामीण-शहरी विभाजन को दूर करने के लिए लक्षित एवं व्यापक रणनीति अपनाएँ। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अटूट प्रतिबद्धता एवं समर्पण को यदि उचित संसाधन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए तो NEP 2020 का स्वप्न — प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा — निश्चित रूप से साकार हो सकता है।

संदर्भ सूची (References)

1. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.

2. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education (formerly Ministry of Human Resource Development). https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

3. Government of India. (2023). Annual report 2022–23. Ministry of Women and Child Development. https://wcd.nic.in/document/annual-report-2022-23

4. Government of India. (2024). Statement indicating state/UT-wise number of operational Anganwadi Centres. Lok Sabha Unstarred Question, Ministry of Women and Child Development. https://www.indiangovtscheme.com/statement-indicating-state-wise-operational-anganwadi-centres/

5. Gupta, R. (2019). Digital Divide in Anganwadi Centres: A Rural-Urban Analysis. Journal of Early Childhood Education, 15(2), 45-62.

6. Lok Sabha Secretariat. (2024). Starred and unstarred questions and replies: Integrated Child Development Services (ICDS). Parliament of India. https://loksabha.nic.in

7. Ministry of Human Resource Development (MHRD). (2020). National Education Policy 2020. Government of India, New Delhi.

8. Ministry of Women and Child Development. (2021). Mission POSHAN 2.0: Operational guidelines. Government of India. https://wcd.nic.in/schemes/mission-poshan-20

9. Ministry of Women and Child Development. (2023). Annual Report 2022-23. Government of India, New Delhi.

10. NITI Aayog. (2021). Strategy for New India @ 75: Education and Skill Development. Government of India.

11. NITI Aayog. (2021). Strengthening early childhood care and education (ECCE) in India. Government of India. https://www.niti.gov.in

12. PRS Legislative Research. (2024). Demand for grants 2024–25 analysis: Ministry of Women and Child Development. https://prsindia.org/budgets/parliament/demand-for-grants-2024-25-analysis-women-and-child-development

13. Ramachandran, V. (2010). Systemic Barriers to Access and Retention: An Analysis of ICDS Programme. Economic and Political Weekly, 45(17), 93-100.

14. Sharma, A., & Verma, S. (2018). Impact of Trained Anganwadi Workers on Cognitive Development of Children: A Comparative Study. Indian Journal of Child Development, 10(1), 21-34.

15. Singh, P. (2022). Integration of NEP 2020 with Early Childhood Care and Education: Opportunities and Challenges. Contemporary Education Dialogue, 19(1), 58-79.

16. UNICEF India. (2022). Early childhood development in India: Status and challenges. https://www.unicef.org/india/what-we-do/early-childhood-development

17. UNICEF. (2020). Early Childhood Development: The Key to a Full and Productive Life. UNICEF India.

18. World Bank. (2018). The State of Early Childhood Education in India. World Bank Group, Washington, D.C.

19. कुमार, ए. (2017). आँगनवाड़ी केंद्रों में बाल विकास सेवाओं का मूल्यांकन। शिक्षा और समाज, 22(3), 112-128.

20. पाण्डेय, आर. एवं मिश्रा, एस. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा: एक विश्लेषण। शैक्षिक अनुसंधान, 8(2), 35-50.

ISSN : 3108-0294